As such, I demand that an office of the South Eastern Railway Public Service Commission should be opened at Cuttack in the State of Orissa.

(iv) Need to enforce provisions of Civil Rights Act.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी लज्जा की बात है कि आज भी देश में, विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में, तथाकथित सवर्णों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रति छुआछूत की भावना बड़े पैमाने पर व्याप्त है। यह और भी बिडम्बना की बात है कि हम अन्य देशों में तो मानवाधिकर की रक्षा के सूत्रधार बन रहे हैं और अपने ही देश में चिराग तले अंधेरा है। देश में छुआछूत के प्रचलन के सम्बन्ध में अभी कुछ समय पूर्व अखिल-भारतीय हरिजन सेवक संघ ने बारह राज्यों में सर्वेक्षण किया है, जिसकी पुष्टि आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति द्वारा भी की जा चुकी है। सर्वेक्षण रपट समस्या की जटिलता पर विस्तृत प्रकाश डालती है। छुआछूत की शिकार जातियों के लोग कुँए से पानी नहीं ले सकते, मन्दिर तथा होटलों में प्रवेश नहीं कर सकते। कहीं कहीं पंचायतों की बैठकों में हरिजन पंचों से अन्य पंच सलाह तक नहीं लेते।

लगभग 6 वर्ष पूर्व सिविल राइट्स एक्ट पारित हुआ था, जिसमें छुआछूत मानने वालों के विरुद्ध कठोर दण्ड का प्रावधान हैं। परन्तु एक्ट की व्यवस्थाओं को कहीं लागू नहीं किया गया और वह निष्प्रभावी हो चुका है। चूँकि समस्या धार्मिक एवं सामजिक अंध-विश्वासों एवं रुढ़िवादिताओं में जकड़ी हुई है, मात्र कानून बना देने से उसका समाधान नहीं निकल सकता।

मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करूँगा कि वह आवश्यकतानुसार सिविल राइट्स एक्ट की व्यवस्थाओं को प्रभावकारी ढंग से लागू कराएं तथा यह प्रयास करें कि सरकार तथा धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर इस कलंक को शीघ्र मिटाया जा सके, अन्यथा हम मानवाधिकार की हिमायत के हकदार नहीं हैं।

(v) Demand for enquiry into termination of Services of workers of Railway Mail Services at Gorakhpur.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे डाक सेवा, गोरखपुर डिवीजन में कार्य कर रहे 1500 कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया जाना गम्भीर चिंता का विषय है। ये कर्मचारी लगभग 9 वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे थे। जहां इन्हें स्थायी रूप से सेवा में ले लिया जाना चाहिये था, वहाँ उन्हें सेवा-निवृत कर दिया जाना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दिनों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को निकालकर नये लोगों की भर्ती करने की जो कार्यवाही चल रही है, वह बहुत ही संदिग्ध है। अतः सरकार से मेरी मांग है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की जाय तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय और जो कर्मचारी गत कई वर्षों से कार्यरत है, उन्हें स्थायी किया जाए। इसके यदि किसी लिये नियम में परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो उसे शीघ्र परिवर्तित किया जाये।

(vi) Need for Financial Grant to Calcutta University.

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY (KATWA) : Sir, The Calcutta University, the Pioneer University in the country and one of our proud national heritages, has been under severe constraint to pursue its developmental process due to acute shortage of space. The University which runs 66 departments and caters to the largest student population in Asia, is 'scatteredly' situated in seven places of Calcutta, and has a total area of 20 acres only. In the early seventies, the Ghani Committee appointed by the University Grants Commission recommended that the University be put into a single campus covering at least 200 acres, and that a sum of Rs. 27.5 crores in the 5th plan and 6th plan periods be granted to construct the integrated campus.

The Government of West Bengal has offered the University a campus of 125 acres of land in the most beautifully, and wellconveyanced area of Calcutta, surrounding which

is situated the National Library, Zoological Garden etc. It has also assured the University all possible help in the matter. The University has drawn a master plan for the new campus, the cost of which has been estimated at Rs. 30 crores, approximately. In late 1981, the University has appealed to the UGC and also to the Central Government, through UGC,to allocate the University Rs. 15 crores in the Sixth Plan, Though the Sixth Plan has already passed the better part of its life, the help to University has not come forth yet. I appeal to the Government to consider this initial grant to the Calcutta University as quickly as possible, and stand by this University of national importance in its endeavour to improve and advance the system of higher education in this country.

(vii) Need for abolition of Public Schools System.

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद जहां शिक्षा जगत में एकरूपता लानी चाहिए थी, उसके विपरीत असमानता में वृद्धि हुई है। आज बड़ी-बड़ी सरकारी सेवाओं में सफल होने वाले शत-प्रतिशत उम्मीदवार पब्लिक स्कूलों के छात्र होते हैं। केंद्रीय विद्यालयों का स्तर भी अच्छा है, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। पब्लिक स्कूल इतने मंहगे हैं कि कोई साधारण व्यक्ति उन विद्यालयों में अपनी संतान के दाखिले की बात सोच भी नहीं सकता है। फलस्वरूप देश की बड़ी सेवायें कुछ परिवारों के हाथों में केन्द्रित होती जा रही हैं। आज जहां करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं, वहां एक एक परिवार में पांच-पाँच आई० ए० एस०, एवं आई० पी० एस० हैं। ये पब्लिक स्कूलों की ही देन है।

आम विद्यालय का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि उस विद्यालय से पढ़ा छात्र क्लर्क भी नहीं बन पाता है। एक तरफ पब्लिक स्कूल और दूसरी ओर सामान्य विद्यालय, यह संविधान के समानता के सिद्धान्त के प्रतिकूल है।

अत: सरकार के मांग है कि समान शिक्षा लाने हेतु संविधान में अविलम्ब संशोधन कर पब्लिक स्कूलों की समाप्ति करे और सामान्य विद्यालय की पढ़ाई का स्तर ऊंचा कर के कम से कम केन्द्रीय विद्यालय के स्तर तक लाए।

(viii) Demand for declaration of Ramanavami as a Gazetted Holiday.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष दिनांक 21 अप्रैल को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन है। भगवान श्री राम की जयन्ती "रामनवमी" सारे देश में उत्साहपूर्वक मनाई जाती है। सम्पूर्ण हिन्दू समाज श्री राम को श्रद्धा और भक्ति से स्मरण कर, पूजा-पाठ, व्रत-उपवास तथा चिन्तन-मनन कर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिये आराधना करता है। किन्तु इस पुनीत पर्व पर सरकारी अवकाश घोषित नहीं किया गया है।

हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्मशून्यता नहीं है। हम सब धर्मों का, उनके महापुरुषों का तथा धर्मग्रन्थों का समान रूप से सम्मान करते हैं। धर्म निरपेक्षता का अर्थ सर्व धर्म समभाव है। हमारे संविधान ने सामाजिक समता और धार्मिक स्वतन्त्रता को महत्व दिया है। हम विविधता में एकता और एकता में एकात्मता विश्वास करते हैं।

हम महात्मा गांधी के सपनों का भारत निर्माण करना चाहते हैं। महात्मा गांधी स्वतन्त्र भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं जिनकी कृति की स्मृति अतीव आवश्यक है।

विश्व हिन्दू परिषद ने महामहिम राष्ट्रपति जी को दस लाख से अधिक हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन भेंट कर भगवान श्री राम के जन्मदिन को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि "रामनवमी" के पावन पर्व पर सरकारी अवकाश घोषित कर देश की एकात्मक के प्रतीक